इंदिरा आवास में कटौती गरीबों के साथ अन्याय

अब भी फूस के घरों में रह रहे हैं 38 लाख परिवार : श्रवण कुमार

पटना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चालू वित्तीय वर्ष से इंदिरा आवास योजना में केंद्रांश को घटा कर 50 फीसदी करने की केंद्र की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इसका असर बिहार जैसे गरीब राज्य पर पड़ेगा। वे शुक्रवार को उपविकास आयुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस साल के लिए इंदिरा आवास के कोटे को घटा कर 2.80 लाख कर दिया है, जबकि अभी राज्य में 38 लाख परिवार फूस और बांस से बने घरों में रह रहे हैं। केंद्र को इस मानक में बदलाव करना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां जीविका को लगभग 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, वहीं 1200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में मात्र 33 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मंत्री ने अधूरे पड़े 12.67 लाख इंदिरा आवास में से 70 फीसदी को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव अमरजीत सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर सुब्रह्मण्यम, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।